राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, झारखण्ड
संयोजक: बैंक ऑफ इंडिया
दिनांक : 10.08.2018
स्थान –होटल रैडिसन ब्लू, रांची

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड के 64 वीं त्रैमासिक बैठक का कार्यवृत्त
Minutes of the 64th Quarterly Meeting of SLBC, JHARKHAND

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड की 64वीं त्रैमासिक बैठक का आयोजन दिनांक 10.08.2018 को होटल रैडिसन ब्लू, रांची में किया गया।

बैठक का आरम्भ राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड के महाप्रबंधक श्री चंद्रशेखर सहाय द्वारा सभा में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों के स्वागत संबोधन से हुआ | श्री सहाय ने अपने संबोधन में भारत सरकार द्वारा हाल ही में संचालित "ग्राम स्वराज अभियान" के द्वितीय चरण के दौरान शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने पर सभी संबंधित बैंको एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों को विशेष रूप से धन्यवाद दिया | उन्होंने वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम तिमाही के दौरान बैंको द्वारा सफलतापूर्वक प्राप्त किये गए लक्ष्यों के लिए बैंको को बधाई दी और जिन क्षेत्रों में बैंको का प्रदर्शन संतोषप्रद नहीं रहा है, उन क्षेत्रों में उनसे बेहतर प्रदर्शन करने की अपील की |

तत्पश्चात मंच पर आसीन झारखण्ड सरकार के विकास आयुक्त श्री डी. के. तिवारी; वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री मदनेश मिश्रा; ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रधान सचिव श्री अविनाश कुमार; योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के सचिव श्री सतेन्द्र सिंह; शहरी विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार के सचिव श्री अजय कुमार सिंह; गृह विभाग, झारखण्ड सरकार की विशेष सचिव श्रीमती तदाशा मिश्रा; भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक एवं OIC श्री संजीव दयाल; नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री शरद झा; बैंक ऑफ़ इंडिया के वित्तीय समावेशन विभाग,प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक श्री शंकर प्रसाद एवं भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक श्री अमूल्य कुमार साहू का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया |

बैठक में उपरोक्त सम्मानित अतिथियों के अलावे झारखण्ड सरकार के अन्य विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारी; झारखण्ड राज्य स्थित सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुख; झारखण्ड राज्य के 24 जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधक एवं विभिन्न बैंकों के उच्च अधिकारी भी उपस्थित थे |

स्वागत कार्यक्रम के पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक एवं OIC श्री संजीव दयाल को बैठक को सम्बोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया।अपने सम्बोधन मे श्री दयाल ने SLBC से राज्य के CD Ratio के साथ साथ प्रत्येक तिमाही के दौरान incremental CD ratio की जानकारी देने का सुझाव दिया | इसके साथ ही उन्होंने राज्य में कार्यरत small finance banks के उपलब्धियों को भी प्रगति प्रतिवेदन में शामिल करने एवं उनके लिए SLBC द्वारा target निर्धारित किये जाने का निर्देश दिया | उन्होंने Agr Sub Committee की बैठक कर राज्य के लिए निर्धारित किये गए ACP के साथ सभी बैंको के business target को synchronize करने की बात कही | उन्होंने सभी बैंको से SLBC को correct

एवं timely data दिए जाने का निर्देश दिया और SLBC से ऐसा न करने वाले बैंकों के लिए agenda book में अलग से comment किये जाने की बात कही।

इसके पश्चात BOI, FI Deptt, HO के महाप्रबंधक श्री शंकर प्रसाद ने अपने संबोधन में सभी बैंको को eGSA में सराहनीय कार्य करने के लिए बधाई दी। उन्होंने दिनांक 04.08.2018 को DFS द्वारा आहूत VC का हवाला देते हुए सम्बंधित बैंको से राज्य में identified सभी locations पर निर्धारित समयावधि के अंदर बैंक की शाखाएं खोलने तथा BC नियुक्त किये जाने का आग्रह किया।

अगले वक्ता के रूप में शहरी विकास एवं आवास विभाग के सचिव श्री अजय कुमार सिंह ने अपने विभाग की दो योजनाओं –NULM एवं PMAY से सम्बंधित आंकड़ों को स्पष्ट करते हुए सभी बैंको से इन योजनाओं में सक्रिय भागीदारी की अपील की और इनको राज्य में सफलतापूर्वक लागू किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया।

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रधान सचिव श्री अविनाश कुमार ने SBI के एक पत्र का हवाला देते हुए बैंकों द्वारा ग्राहकों के लिए KYC/eKYC की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए RBI एवं अन्य सम्बंधित विभागों से सुचारू नीति बनाये जाने की अपील की। उन्होंने बैंको द्वारा जनधन खातों को सामान्य खातों में परिवर्तित नहीं किये जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। सखी मंडलों के लंबित आवेदनों के शीघ्र निष्पादन की बात करते हुए उन्होंने कई बैंको द्वारा इन आवेदनों को receive करने में तत्परता नहीं दिखाए जाने पर भी असंतोष प्रकट किया। उन्होंने न्सभी बैंको से आग्रह किया कि पूरे राज्य में सभी इलाकों को BC/CSP से आच्छादित करें ताकि इनका presence स्वतः दिखाई दे। उन्होंने गढ़वा जिले में PMAY योजना के तहत हो रहे fraud पर सभा का ध्यान आकृष्ट कराया और साथ ही राज्य के sensitive इलाकों में प्रखंड अधिकारियों से समन्वय कर cash की उपलब्धता सुनिश्चित करने की हिदायत दी।

गृह विभाग के विशेष सचिव श्रीमति तदाशा मिश्रा ने अपने संबोधन में ग्रामीण शाखाओं को आर्थिक विकास का मुख्य श्रोत बताते हुए वहां सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने की बात कही। उन्होंने बैंको से राज्य के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की और साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि बैंको को अपने कार्य कलाप अथवा ऋण वसूली में जहाँ भी सुरक्षा की जरुरत महसूस होगी, वहां सरकार द्वारा समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी।

विकास आयुक्त श्री डी. के. तिवारी ने सभी बैंको को वित्तीय समावेशन, विशेषतः ग्राम स्वराज अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बधाई देते हुए कतिपय मुद्दों की तरफ SLBC एवं अन्य हितधारकों का ध्यान दिलाया। उन्होंने SLBC को विभिन्न sub committees में हुई चर्चा के आधार पर SLBC की मीटिंग के लिए agenda items को चिन्हित करने का सुझाव दिया और सरकार से सम्बंधित मुद्दों को meeting से यथासंभव पहले सम्बंधित विभागों को उपलब्ध करने का निर्देश दिया ताकि उन मुद्दों पर यथोचित कार्यवाही करने के लिए विभागीय अधिकारियों को पर्याप्त समय मिल सके। उन्होंने पिछले 10-12 meeting के कार्यवृत की चर्चा करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि SLBC की meeting बहुत सार्थक न होकर महज एक routine की तरह हो गया है, जहाँ लगातार एक ही तरह के मुद्दों की केवल चर्चा की जाती है परन्तु उसके समाधान का कोई ठोस प्रयास नहीं किया जा रहा है। SHG financing की चर्चा के क्रम में उन्होंने slbc से इस sector में स्वीकृत राशि एवं वर्तमान बकाया शेष के साथ साथ वितरित की गयी राशि का भी उल्लेख करने का निर्देश दिया। उन्होंने SLBC की meeting में special guests/acamedicians को बुलाये जाने की बात पर चर्चा करते हुए कहा कि कभी-कभी सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत ऋण प्राप्त किये गए लाभार्थियों को इन meetings में बुलाया जाना चाहिए ताकि उनके अनुभवों को सभी हितधारकों के साथ साझा किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने SLBC को विभिन्न बैंको/शाखाओं/बैंक मित्रों के द्वारा किये गए उपलब्धि के आधार पर उनकी ranking निर्धारित करने और साथ ही non-performing बैंको/अधिकारियों/अग्रणी जिला प्रबंधकों की भी

State Level Banker Committee BOI Jharkhand

जानकारी दिए जाने का सुझाव दिया, जिससे एक प्रकार का incentivisation structure develop हो सके। उन्होंने SLBC को निर्देश दिया कि 40% से कम CD ratio वाले बैंको/जिलों में Monitorable Action Plan के आधार पर किये जाने वाली कार्यवाहियों से सरकार को अवगत कराया जाये। उन्होंने सभी जिलों में निर्धारित तिथि पर BLBC/DCC/DLRC की बैठक सुनिश्चित करने और वहां उठाये गए सभी लंबित मुद्दों के समाधान के लिए SLBC की meeting में विस्तृत चर्चा करने का निर्देश दिया। उन्होंने सखी मंडल की महिलाओं को BC के रूप में नियुक्त किये जाने, कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाये जाने, RSETI के निर्माणाधीन भवनों को निश्चित समय सीमा तय कर पूर्ण किये जाने, बैंको द्वारा कौशल विकास केन्द्रों के साथ coordination किये जाने एवं ग्राम/आदिवासी विकास समितियों का खाता खोले जाने की की भी बात कही। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने DFS से यह आग्रह किया कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत DBT के माध्यम से दिए जा रहे सहायता राशि का लंबित ऋण खातों में समायोजन कर लिए जाने के मुद्दे पर कोई व्यवस्था बनायी जाये जिससे इन योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई बाधा न आने पाए।

वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री मदनेश मिश्रा ने अपने संबोधन में ग्राम स्वराज अभियान की सफलता के लिए सभी बैंको की सराहना की और हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग के क्षेत्र में किये गए वित्तीय प्रबंधन से सम्बंधित कुछ सुधारों की चर्चा की। उन्होंने अपने संबोधन में विकास आयुक्त और ग्रामीण विभाग के प्रधान सचिव द्वारा उठाये गए कुछ मुद्दों पर वस्तुस्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं के तहत DBT के माध्यम से दिए जा रहे सहायता राशि का लंबित ऋण खातों में समायोजन कर लिए जाने के मामले पर RBI के साथ विचार चल रहा है और जल्द ही इस समस्या के समाधान हेतु कोई उपाय कर लिए जाने की संभावना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बैंको द्वारा KYC के लिए नियत प्रावधानों के तहत की गयी कार्यवाही को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता है परंतू नियत प्रावधानों से इतर किसी भी तरह से ग्राहकों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जन धन खातों अथवा BSBD a/cs में सरकारी राशि के जमा/निकासी पर बैंको द्वारा लगायी जानेवाली पाबन्दी पूर्णतः नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने DCC/DLRC की बैठकों में उठाये गए मुद्दों को प्रमुखता के साथ SLBC को भेजे जाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि उन मुद्दों पर सार्थक कार्यवाही हो सके। इसके अभाव में उन्होंने इन बैठकों के आयोजन को महज औपचारिकता बताया। उन्होंने SLBC की प्रत्येक बैठक में किसी एक agenda item पर focus करने की सलाह दी ताकि उसका त्वरित और उचित समाधान निकला जा सके। उन्होंने सभी बैंको एवं LDMs से BC के deployment को rationalize किये जाने की बात कही। श्री मिश्रा ने सभा को बताया कि रांची को smart city के रूप में develop करने के लिए चिन्हित किया गया है और PMO के द्वारा इसकी बार-बार समीक्षा की जाती है, अतः सभी बैंको को शत प्रतिशत digitization के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। कई जिलों और बैंको के कम CD ratio पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सम्बंधित बैंको एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा Monitorable Action Plan बनाकर इस दिशा में अविलम्ब प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने कुछ जिलों का नाम उद्धृत करते हुए कहा कि लगभग सभी parameters में इन्ही जिलों का performance औसत से नीचे है, अतः इन जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधकों एवं सम्बंधित बैंको को अतिरिक्त प्रयास कर स्थिति में सुधार लाना पड़ेगा। कई तरह के डाटा बैंको द्वारा लेने में SLBC को आ रही कठिनाई पर उन्होंने SLBC को पोर्टल बनाने का सुझाव दिया जिसपर सम्बंधित बैंक अपने आंकड़े नियमित अन्तराल पर अपडेट करते रहें। अंत में उन्होंने सभी बैंको को PMSBY एवं PMJJBY के साथ साथ APY में भी ज्यादा से ज्यादा subscribers को enroll किये जाने का निर्देश दिया।

<u>व्यवसाय सत्र (Business Session):</u> मुख्य प्रबंधक, SLBC, श्री दीप शंकर द्वारा व्यवसाय सत्र की कार्यवाही शुरू करते हुए सर्वप्रथम सभाध्यक्ष महोदय द्वारा उठाये गए बिन्दुओं /सुझावों के आलोक में अगली SLBC की बैठक से पूर्व आवश्यक सुधार कर लिए जाने का आश्वाशन दिया गया। सभा को बताया गया कि बैंको से सम्बंधित आंकड़े नियत समय के अंदर नहीं मिलने के कारण SLBC के agenda items एवं data को तैयार करने में देरी होती है। इसपर सभाध्यक्ष महोदय ने अगली बार से एक निश्चित समय

सीमा तक प्रतीक्षा करने के उपरांत ऐसे बैंको के आंकड़े को बिना सम्मिलित किये ही book तैयार करने का निर्देश दिया और इन बैंको के प्रधान कार्यालयों को सूचित करने का निर्देश दिया |
इसके पश्चात् दिनांक 15.05.2018 को आयोजित 63वी एसएलबीसी बैठक के कार्यवृत की संपुष्टि सभा द्वारा करायी गयी |

राज्य सरकार से संबंधित मामले:

इसके बाद राज्य सरकार से संबंधित मामलों की चर्चा की गई :

क्रम संख्या	विषय	निष्कर्ष	कार्यवाही के लिए चिन्हित विभाग
1.	पंचायत भवन मुख्यालयों में ATM की व्यवस्था	हर जिले में ATM की आवश्यकता वाले पंचायतों/स्थानों का अग्रणी जिला प्रबंधकों/बैंको के द्वारा चयन	अग्रणी जिला प्रबंधक/बैंक/SLBC
2.	Dedicated Certificate Officer की नियुक्ति का मामला	कार्यालीय खर्च की प्रतिपूर्ति बैंको द्वारा नहीं करके वसूली गयी राशि से एक निश्चित रकम सरकार के खाते में दिया जाना	राज्य सरकार
3.	बैंको को सरकारी भूमि के आवंटन में कीमत का मामला	आवंटित भूमि के पूर्व में और वर्तमान में दिए गए क्रय में मूल्य के अंतर पर अंतिम निष्कर्ष हेतु सम्बंधित विभाग के साथ बैंको की बैठक	राज्य सरकार
4.	SARFAESI के अंतर्गत physical possession के लिए लंबित cases	जिले के अधिकारियों के साथ बैठक किया जाना प्रस्तावित	राज्य सरकार
5.	वित्तीय शिक्षा को स्कूल के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में	वित्तीय शिक्षा को स्कूल के पाठ्यक्रम में जल्द ही सम्मिलित किया जायेगा	राज्य सरकार

बैंकसेसंबधितमामले / Issues Pertaining To Banks

सभा को बताया गया कि Bandhan Bank, Federal Bank, Indus Ind Bank, J & K Bank, Karur Vaisya Bank, Kotak Mahindra Bank, Laxmi Vilas Bank, South Indian Bank और Yes Bank ने बार-बार लिखित एवं मौखिक आग्रह के बावजूद SLBC को ATR प्रेषित नहीं किया | RBI के महाप्रबंधक एवं OIC श्री संजीव दयाल ने इन सभी बैंको के प्रधान कार्यालय को इस सम्बन्ध में SLBC द्वारा पत्र लिखने की बात कही |

कार्यवाही के मध्य में IG, Operations, झारखण्ड पुलिस, श्री आशीष बत्रा ने पलामू में चिन्हित किये गए 06 बैंक शाखाओं के खोले जाने में हो रही देरी पर सभा का ध्यान आकृष्ट कराया | उन्होंने राज्य में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार हो रहे सुधारों के मद्देनज़र बैंको से वित्तीय समावेशन के लिए और अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता बताई | उन्होंने साथ ही SLBC को 250 वैसे centres की जानकारी देने का आश्वाशन भी दिया जहाँ CRPF के कैंप हैं और जहाँ security measures को देखते हुए ATMs/ Banking Outlets की व्यवस्था करना ज्यादा सुविधाजनक होगा | सभाध्यक्ष ने इसपर यथोचित कार्यवाही करने हेतु SLBC को निर्देशित किया |

तत्पश्चात श्री दीप शंकर ने एसएलबीसी की 63वीं बैठक में चर्चा किए गए बिंदुओं पर बैंक से प्राप्त Action Taken रिपोर्ट को क्रमवार प्रस्तुत किया, जिसपर किये गए discussion और आगे की जानेवाली अपेक्षित कार्यवाही का ब्यौरा निचे प्रस्तुत किया जा रहा है:

1. eGSA- सभा को बताया गया कि eGSA के तहत केवल साहिबगंज जिले के कुछ गाँवों को छोड़कर बाकि सभी गाँवों में saturation हो गया है और साहिबगंज में भी अगले 2-3 दिनों के अंदर यह कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। **(Action: VGB एवं LDM, Sahibganj)**

2. PMFBY- सभी बैंको से सभी loanee farmers को insurance coverage दिये जाने और उससे संबंधित रिपोर्टिंग पोर्टल पर विधिवत तरीके से किये जाने का अनुरोध किया गया। चर्चा के क्रम में विकास आयुक्त ने PMFBY के तहत दिए जाने वाले किसानों के अंशदान को राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने की जानकारी दी। कृषि निदेशक, झारखण्ड सरकार ने सभी बैंको से promt repayment के cases में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली interest subsidy का claim State Co-operative Bank (Nodal Agency) से अविलम्ब कर लिए जाने की अपील की। **(Action:सभी संबंधित बैंक)**

3. CGTMSE coverage- बैंको से सभी eligible cases में CGTMSE coverage लिए जाने और उसकी सही रिपोर्टिंग किये जाने का आग्रह किया गया। **(Action:सभी संबंधित बैंक)**

4. मुद्रा प्रोत्साहन अभियान- बार-बार मौखिक एवं लिखित आग्रह और अग्रिम मे सूचना दिये जाने के बावजूद दिनांक 12.10.2017 को मोराबादी में आयोजित मुद्रा प्रोत्साहन अभियान में हुए खर्च के विरुद्ध IOBने अब तक अपना contribution रु 77400/- की राशि SLBC को प्रेषित नहीं की है। **(Action: IOB)**

5. बैंको को अपने सेवा क्षेत्रों में पड़ने वाले villages को agriculture purpose से adopt करने की सलाह दी गई ताकि वहाँ कृषि ऋण के प्रवाह को बढाया जा सके। **(Action:सभी बैंक)**

6. मुख्यमंत्री जन संवाद –सभी बैंको से आग्रह किया गया कि जन संवाद के तहत जनता से प्राप्त शिकायतों को त्वरित और प्रभावी ढंग से निष्पादित किया जाये अन्यथा कभी कभी कुछ मुद्दे काफी गंभीर हो जाते हैं और बैंको को विषम परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। **(Action:सभी बैंक)**

7. SLBC द्वारा NABARD से यह अनुरोध किया गया कि वास्तविक उपलब्धि और potential के आधार पर सभी बैंको की सहभागिता से ही PLP बनाया जाना चाहिए। इस पर NABARD द्वारा सुझाव दिया गया कि अगले 10 दिनों के अंदर Agr Sub Committee की बैठक कर इसमें यथासंभव सुधार करने का प्रयास किया जायेगा। विकास आयुक्त ने DFS के सुझाव के आधार पर अगली SLBC की बैठक में agr credit growth पर special focus करने का निर्देश दिया और साथ ही बैंको के performance को highlight करने का सुझाव दिया। **(Action: NABARD, SLBC एवं बैंक)**

सभी बैंको के महत्वपूर्ण संकेतक

इस विषय पर सभा को बताया गया कि राज्य में पिछले तिमाही जनवरी-मार्च की तुलना में अप्रैल-जून तिमाही में ऋण प्रवाह में वृद्धि होने के बावजूद CD ratio में कमी आई है जो मुख्यतः HDFC बैंक द्वारा Place of utilization के अंतर्गत पिछली तिमाही में दर्शाए गए रु 3567 करोड़ के विरुद्ध इस तिमाही में दर्शाए गए शून्य राशि के कारण हुआ है। विकास आयुक्त द्वारा HDFC बैंक से जानकारी मांगे जाने पर HDFC के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति का मामला सामने आया जिसपर विकास आयुक्त ने HDFC को पत्र लिखने का निर्देश दिया। महिलाओं एवं अल्पसंख्यक समुदायों को दिये जाने वाले ऋण से संबंधित रिपोर्टिंग में कई बैंको द्वारा काफी variation किये जाने की तरफ सभा का ध्यान आकृष्ट कराया गया और सभी से इस पर ध्यान देने की अपील की गई। **(Action: SLBC , सभी बैंक)**

वार्षिक ऋण योजना के आधार पर वर्ष 2018-19 की उपलब्धि की समीक्षा

इस विषय पर मुख्य प्रबन्धक श्री दीप शंकर ने जानकारी देते हुए बतलाया कि reporting quarter के दौरान बैंको ने ACP target के विरुद्ध लगभग 28.50 % achievement कर लिया है । कृषि क्षेत्र में बैंको के द्वारा अपेक्षाकृत संतोषप्रद प्रदर्शन नहीं होने के कारण और विकास आयुक्त द्वारा अगली SLBC

के लिए agr credit growth पर prime focus दिए जाने सम्बन्धी निर्देश के आलोक में SLBC द्वारा सभा को बताया गया कि जल्द ही NABARD के तत्वाधान में सभी सम्बंधित हितधारकों के साथ बैठक कर इस दिशा में अपेक्षित प्रगति के लिए ठोस उपाय किये जायेंगे। **(Action: सभी बैंक, सभी LDMs, NABARD, SLBC एवं RBI)**

कृषि ऋण एवं किसान क्रेडिट कार्ड

राज्य में कृषि ऋण का प्रवाह बढ़ाये जाने की दिशा में यूनियन बैंक द्वारा बिना LPC के KCC ऋण देने की वर्तमान सीमा रु 1.00 लाख से बढ़ाये जाने का सुझाव दिया गया , जिसपर कृषि निदेशक ने विभाग से विचार कर इस पर जल्द ही कोई निर्णय लिए जाने का आश्वाशन दिया। PNB द्वारा राज्य में land records को अद्यतन (dizitization) किये जाने के बावजूद इसके regular updation नहीं किये जाने के कारण वास्तविक जमीन मालिक के सही पहचान में आ रही कठिनाई का मामला उठाया गया। NABARD के प्रतिनिधियों द्वारा कृषि ऋण में अपेक्षित वृद्धि के लिए landless farmers को और JLG mode में ज्यादा से ज्यादा ऋण दिए जाने की बात कही गयी।

(Action: राज्य सरकार, NABARD एवं बैंक)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना/ स्टैड अप इंडिया ऋण योजना

सभी बैंको से PMMY के तहत DFS द्वारा दिए गए बजट को district wise allocate कर SLBC को प्रेषित करने का आग्रह किया गया। श्री मदनेश मिश्रा ने मुद्रा योजना के तहत दिए गए नए ऋण का अलग से और साथ ही साथ ऋण प्राप्त लाभार्थियों द्वारा generate किये गए employees की संख्या का आंकड़ा उपलब्ध कराने को कहा । साथ ही उन्होंने SUI योजना के तहत राज्य में अब तक हुई कम उपलब्धि पर भी अपना असंतोष प्रकट किया । उन्होंने राज्य सरकार से इस योजना के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों के margin money को arrange करने के लिए किसी तरह का प्रावधान करने की बात कही।

(Action: राज्य सरकार, SLBC, सभी बैंक)

एसएचजी महिलाओं के वित्त पोषण हेतु योजना

सभी बैंको से यह आग्रह किया गया कि वे SHG financingकी reporting में स्वीकृत राशि एवं वर्तमान बकाया शेष के साथ साथ वितरित की गयी राशि का भी उल्लेख करें। **(Action: सभी बैंक)**

वित्तीय समावेशन/प्रधानमंत्री जन धन योजना

SLBC द्वारा सभा को बताया गया कि झारखण्ड में सभी 4178 SSA या तो BC या फिरबैंक की शाखा के through covered हैं। इसके साथ ही BC द्वारा no. of transaction एवं Rupay कार्ड activation को बढ़ाये जाने की बात पर बल दिया गया। कई जगहों पर कई बैंको के द्वारा BC की नियुक्ति में आ रही परेशानी को देखते हुए SLBC द्वारा SSAs के alottment का fresh exercise किये जाने की आवश्यकता बताई गयी। सभी बैंको एवं LDMs से जल्द से जल्द हर uncovered area को BC के द्वारा covered किये जाने एवं BCs के detail को SLBC के साथ share किये जाने का आग्रह किया गया ताकि इन आंकड़ों को SLBC के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा सके।

(Action:SLBC,सभी संबंधित बैंक एवं LDMs)

गैर निष्पादनीय आस्तियां

राज्य सरकार से लंबित पड़े certificate cases एवं SARFAESI cases के त्वरित निष्पादन का आग्रह किया गया।

(Action: राज्य सरकार एवं बैंक)

PMEGP/PMAY/NULM

SLBC द्वारा सभी बैंको से इन schemes के तहत लंबित आवेदनों के अतिशीघ्र निष्पादन का आग्रह किया गया । शहरी विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों द्वारा सभी बैंको से जून 2015 के बाद स्वीकृत वैसे Housing Loans जो PMAY की पात्रता रखते हैं उन्हें PMAY स्कीम में लाकर उसमे मिलने वाली subsidy की राशि claim कर लिए जाने की बात दोहरायी गयी। इसके साथ ही PMAY के लिए

इच्छुक 16000 लाभार्थियों से contact करने का आग्रह किया गया जिनके details बैंको को भेजे गए हैं ताकि PMAY ऋण स्वीकृति की स्थिति में अपेक्षित गति लायी जा सके। **(Action: सभी बैंक)**

RSETI एवं FLCC

RSETI trained candidates के ऋण आवेदनों को यथाशीघ्र निष्पादित करने के लिए सभी से आग्रह किया गया और साथ ही यह निश्चित करने को कहा गया कि ऐसे किसी भी आवेदन को शाखा स्तर से reject नहीं किया जाये।

(Action: सभी संबंधित बैंक एवं LDMs)

SLBC की विभिन्न उपसमितियों के कामकाज

SBI से आग्रह किया गया कि सुरक्षा और आवास पर बनी उपसमिति की बैठक अविलम्ब करायी जाये। साथ ही NABARD से agr उपसमिति की बैठक जल्द से जल्द करने का अनुरोध किया गया।

(Action: SBI एवं NABARD)

विविधकार्यसूची

1. RBI से लिखित दिनांक 06.08.2018 के पत्र का हवाला देते हुए गढ़वा, पलामू, लातेहार और साहिबगंज के LDMs से जून quarter का DCC/DLRC meeting अविलम्ब कराये जाने का अनुरोध किया गया।

(Action: LDMs- गढ़वा, पलामू, लातेहार और साहिबगंज)

सभा में Indian Bank के प्रतिनिधि द्वारा NABARD को कृषि ऋण देने पर किये जाने वाले modification के लिए अपने मुख्य प्रबंधक श्री संतोष कुमार द्वारा सहयोग दिए जाने का आश्वासन दिया गया।

सभा के अंत में eGSA की सफलता पर सभी गणमान्य अथितियों की मौजूदगी में सर्वप्रथम अपने लक्ष्य को पूरा करने वाले गोड्डा के LDM श्री आर. के. सिन्हा के द्वारा cake cutting ceremony की गयी।

(विन्सेंट लकड़ा)
उपमहाप्रबंधक, रा.स्त.बै.स.

LIST OF PARTICIPANTS IN 64th STATE LEVEL BANKERS' COMMITTEE, JHARKHAND (MEETING HELD ON 10.08.2018)

SR. NO.	NAME OF PARTICIPANTS	BANK / DEPARTMENT	DESINGNATION
1	Sri D K Tiwari		Development Commissioner
2	Sri M. K. Mishra	Joint Secretary	Department of Financial Services
3	Sri Satendra Singh	Secretary	Department of Planning Cum Finance
4	Sri Avinash Kumar	Principal Secretary	Department of Rural Development
5	Sri Sanjiv Dayal	General Manager OIC	Reserve Bank of India
6	Sri Sharad Jha	Chief General Manager	NABARD
7	Sri C S Sahay	General Manager	SLBC Jharkhand
8	Sri Shanker Prasad	General Manager	Bank of India
9	Smt Tadasha Mishra	Spl. Secretary	Department of Home, Jail & Disaster Management
10	Sri A K Sahu	General Manager	State Bank of India
11	Sri Ajay Kr Singh	Secretary	Department of Urban Development
12	Sri Partha Mandal	Dy General Manager	NABARD
13	Sri Ashish Batra	IG	Jharkhand Police
14	Sri Paritosh Upadhyay	Spl. Secretary & CEO	Rural Development
15	Sri Manoj Kumar	Director	Social Welfare
16	Sri R R Tiwary	Asst General Manager	Reserve Bank of India
17	Sri Sanjay Shrivastava	Dy General Manager	State Bank of India
18	Sri Manoj Kumar	Chief Manager	Vijaya Bank
19	Sri Abhishek Kumar	Sr. Manager	Bank of Maharshtra
20	Sri Thomas Minz	Sr. Manager	Oriental Bank of Commerce
21	Sri Surjit Minz	Sr. Manager	Bank of Baroda
22	Sri Abinash Kumar	Chief Manager	Bank of Baroda
23	Sri Amrendra Kumar	Sr. Manager	HUDCO
24	Sri Pratap Ch Kichingia	Joint Secretary	Revenue Dept
25	Sri Ajith Kumar K	Regional Chief	HUDCO
26	Sri Bimal Rath	Regional Resident Representative	National Housing Bank
27	Sri Kali Charan Das	Lead District Manager	Koderma
28	Sri Sanjeev Kumar	Lead District Manager	Ramghar
29	Sri M K Das	Lead District Manager	Chatra
30	Sri Falguni Rai	Lead District Manager	East Singhbhum
31	Sri Sudhir Kumar Das	Lead District Manager	Hazaribagh
32	Sri Preety Ekka	Asst Manager	Indian Overseas Bank
33	Sri Sanjay Shrivastava	Officer	State Bank of India
34	Sri Amit Kumar	Chief Manager	Dena Bank
35	Sri Thomas Dung Ding	Dy Secretray	Food Civil Supply
36	Sri Ram Sagar Pandey	Cluster Head	Bandhan Bank
37	Sri Sunit Kumar	Relationship Manager	Indusind Bank
38	Sri Subhash Kumar	Regional Head	Indusind Bank
39	Sri Abhishek Verma	Cluster Head	Yes Bank
40	Sri Sabbir Akhter	Regional Head	ICICI Bank
41	Sri Rajesh Kumar Singh	Asst Manager	Union Bank
42	Sri Prabir Sengupta	Manager Advance	Vananchal Gramin Bank
43	Sri Narendra Senapati	Divisional Manager	Canara Bank
44	Sri Kumar Sanjeev	Sr Manager	Canara Bank
45	Sri Saloni Singh Pahwa	State Mission Manager	Urban Dev and Housing Dept
46	Sri Prem Trigunait	Regional Operation Manager	Jana Bank
47	Sri Sushant Raj	Area Manager	Ujjivan Samll Finance Bank
48	Sri Ashish Bhusan Das	DM	Ujjivan Samll Finance Bank
49	Sri Chandan Arora	Branch Head	Utkarsh Small Finance
50	Ms Vishakha Chatterjee	Branch Head	Jana Bank
51	Sri Rabish Kumar	Asst Manager	Karur Vysya Bank
52	Sri Rajeev Ranjan	Asst Manager	Lakshmi Vilas Bank
53	Sri Amit	Branch Manager	Federal Bank
54	Sri Tumul Tara	State Mission Manager	Urban Dev and Housing Dept
55	Sri Mukesh Kumar Jha	Social Development	Urban Dev and Housing Dept

R. NO.	NAME OF PARTICIPANTS	BANK / DEPARTMENT	DESINGNATION
56	Sri Amit Kumar Pandey	Asst Branch Manager	Karnataka Bank
57	Sri S B Ahmed	Branch Head	J & K Bank
58	Sri C S D Paan	Lead District Manager	Latehar
59	Sri Kishore Tirkey	Lead District Manager	Palamu
60	Sri Awadhesh Kr Choudhary	Lead District Manager	Garhwa
61	Sri Shudhanshu Shekhar Pathak	Lead District Manager	Jamtara
62	Sri S L Baitha	Lead District Manager	Jamtara
63	Sri R K S Sinha	Lead District Manager	Deoghar
64	Sri Sanjay Kr Sinha	Lead District Manager	Ranchi
65	Sri Ravi Kant Sinha	Lead District Manager	Lohardaga
66	Sri S K Sai	Lead District Manager	Gumla
67	Sri Sudhanwa Mishra	Lead District Manager	Simdega
68	Sri Rajesh Kumar Diwedi	Lead District Manager	Dumka
69	Sri Raman Kumar Sinha	Lead District Manager	Godda
70	Sri Vikash Kumar Singh	Lead District Manager	Pakur
71	Sri Ram Das Rajak	Lead District Manager	Sahebganj
72	Sri Amit Kumar	Lead District Manager	Dhanbad
73	Sri Asharfi Paswan	Lead District Manager	Bokaro
74	Sri Rakesh Singh	Lead District Manager	Giridih
75	Sri S N Mohanty	Lead District Manager	Seraikela
76	Sri Fudan Murmu	Lead District Manager	West Singhbhum
77	Sri Mukesh Kumar	Chief Manager	Corporation Bank
78	Sri Sanjiv Kumar	Sr Manager	Punjab & Sindh Bank
79	Sri Anshul Anand	Manager	Indian Bank
80	Sri Sanjay Kumar Sinha	Sr Manager	Indian Bank
81	Sri Vishal Kumar	Manager	South India Bank
82	Sri P K Gupta	Director	MSME DI
83	Sri Praveen Kumar	Asst Director	Khadi & VI Commission
84	Sri Dhiraj Kr Horo	State Program Manager	JSLPS
85	Sri Sudhanshu Kumar	AVP & Nodal Officer	Axis Bank
86	Sri Surendra Kr Das	Regional Manager	Syndicate Bank
87	Sri Ch. Sriniwasa Sastry	Zonal Manager	Andhra Bank
88	Sri Nandan Kumar	Chief Manager	State Bank of India
89	Sri Sanjay Kr. Sinha	Asst General Manager	State Bank of India
90	Sri Prabhat Kr Singh	Asst General Manager	UCO Bank
91	Sri Rajat Gupta	Chief Manager	Allahabad Bank
92	Sri Sanjib Sarkar	Chairman	Jharkhand Gramin Bank
93	Sri Rajiv Nayan Sinha	Chief Manager	Jharkhand Gramin Bank
94	Sri Ravi Prakash	General Manager	Vananchal Gramin Bank
95	Sri Bibhaw Kumar	Manager	Bank of India
96	Sri Praveen Kumar Jain	Circle Head	Punjab National Bank
97	Sri Ankesh Jain	Regional Head	Union Bank
98	Sri Parikshita Panda	Asst General Manager	United Bank of India
99	Sri Anil Kr Suman	DRM	Central Bank of India
100	Sri Subodh Kumar	Dy General Manager	Canara Bank
101	Sri Rahul Kumar	Under Secretary	Finance Dept
102	Sri Vincent Lakra	Dy General Manager	SLBC
103	Sri Atul Kumar	Field General Manager	Union Bank
104	Sri S B Jena	Field General Manager	Allahabad Bank
105	Sri Deo Shanker	ADG	UIDAI
106	Sri Ramesh Gholap	Director	Agriculture Dept
107	Sri Shubhra Verma	Spl. Secretary	Agriculture Dept
108	Sri Tejeswer Patnaik	Zonal Manager	Bank of India
109	Sri Suryanshu Verma	Asst Vice President	HDFC Bank

State Level Banker Committee ★ Jharkhand ★